



DAILY NEWS BULLETIN

LEADING HEALTH, POPULATION AND FAMILY WELFARE STORIES OF THE Day
Tuesday 20260922

New escalators, streetlights and Ayush hospital get NDMC nod

Vibha.Sharma@timesofindia.com

New Delhi: New Delhi Municipal Council (NDMC) has approved a series of proposals to improve public infrastructure and civic services, including Rs 18.2 crore for eliminating 700 'dark spots' on roads, a 50-bed Ayush Hospital in Sarojini Nagar, and a computer-based examination centre in Moti Bagh.

The council has also cleared a 50% concession in parking charges for electric vehicles (EVs) and approved a proposal to divide its 150 parking facilities into three clusters to expedite the appointment of concessionaires.

The decisions were taken Monday at its first meeting of this financial year. Delhi minister Parvesh Verma administered the oath of allegiance to NDMC chairman Manoj Kumar Dwivedi, who had assumed charge on Aug 7.

Verma said, "Today's decisions will strengthen civic infrastructure and improve everyday services for residents. Our focus is to make New Delhi cleaner, better managed and more citizen-centric."

NDMC vice-chairman Kuljeet Chahal said it identified several locations with inadequate lighting. Under the dark spot elimination project, new octagonal streetlights will be installed. "This will improve public safety," he said.

To encourage the adoption of cleaner transport, NDMC approved a 50% concession in parking charges for electric vehicles at its lots. The initiative is also in line with directions issued by CAQM.

NDMC has been operating parking facilities through its own staff for more than two years, a system that has reportedly resulted in financial

losses. It made several attempts to invite tenders, but couldn't do so. "The proposed smart parking system will help motorists locate available parking spaces through navigation facilities, reduce time spent searching for parking and improve parking management. It will be monitored through its integrated command and control centre. A proposal to revise parking charges is also under consideration," said Chahal.

The council approved a one-time waiver scheme for late payment surcharge on outstanding water bills of Dhobi Ghat consumers. As of April 2026, Rs 63.5 crore was outstanding in water dues. It also okayed a simplified water tariff structure for Dhobi Ghats by removing the earlier applicable charge of 2.5 times the water usage rate. "These steps will provide people relief from the burden of long-pending dues and make the system more reasonable," Verma said.

NDMC okayed a proposal to establish a 50-bed Ayush Hospital and Research Centre in Sarojini Nagar at an estimated Rs 55 crore through a 50:50 partnership between it and ministry of housing and urban affairs.

It proposed setting up a modern computer-based test centre in Moti Bagh. To be named Palika Adarsh Examination Centre, it will conduct computer-based exams for students and is expected to generate revenue for the civic body.

The council also sanctioned Rs 6 crore for replacing seven heavy-duty outdoor/public service escalators in Connaught Place.

Dwivedi said the council approved the draft of NDMC's Solid Waste Management Bye-Laws, 2026, apart from clearing proposals for the construction, operation and maintenance of bus queue shelters.

यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन के शोध में खुलासा, नकारे जाने की आशंका से घिरे लोग ज्यादा संवेदनशील

खुद को कमजोर मानने वाले दूसरों का चेहरा पढ़ने में ज्यादा माहिर

लंदन। जब कोई आपसे बात करते समय यह बोले कि वो बहुत बहादुर है, किसी से नहीं डरता या फलां काम तो बाएं हाथ का खेल है तो कई बार इस पर खीज उठना स्वाभाविक है। लेकिन आपने शायद ही कभी ऐसा महसूस किया होगा कि आपके चेहरे पर नाराजगी का भाव उभरने से पहले ही ऐसी डींगें भरने वाले चुप हो जाते हैं।

दरअसल, एक नए अध्ययन में पता चला है कि खुद को अंदर से कमजोर मानने वाले और लोगों के सामने बहादुरी का दावा करने वाले ज्यादा संवेदनशील होते हैं। सामने वाले के चेहरे पर गुस्से या घृणा का भाव वो तुरंत भांप जाते हैं। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन की तरफ से हाल ही में किए गए एक अध्ययन में



अस्वीकृति के डर से बढ़ा लेते हैं सामाजिक दूरी

डॉ. कोर्जेनियोव्स्का ने बताया, जब किसी व्यक्ति का अचेतन आत्म-सम्मान कम होता है, तो उसका दिमाग संभावित सामाजिक अस्वीकृति से बचने के लिए लगातार अलर्ट मोड पर रहता है। शोध में सामने आया कि चेहरे पर घृणा के भावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील लोग नकारे जाने के डर से एक सामाजिक दूरी बना लेते हैं।

पाया गया कि जिन लोगों के मन में अपने आत्म-सम्मान को लेकर अचेतन रूप से संदेह होता है, वो इस बात को बहुत जल्द समझ जाते हैं कि सामने

वाले को उसकी बात अच्छी लग रही है या नहीं। विज्ञान पत्रिका पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, सामाजिक रूप से

क्या है चेतन व अचेतन आत्म-सम्मान?

शोधकर्ताओं के मुताबिक, आत्म-सम्मान केवल वह नहीं है जो हम ऊपर से महसूस करते हैं या दूसरों को बताते हैं। मनोविज्ञान इसे दो मुख्य हिस्सों में बांटता है।

■ स्पष्ट या चेतन आत्म-सम्मान वह भावना है जिसके बारे में हम सचेत होते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति खुद को योग्य या प्रतिभाशाली मानता है और इसे शब्दों में बयां कर सकता है।

■ अन्तर्निहित या अचेतन आत्म-सम्मान मन के भीतर की वो भावना है जिसमें व्यक्ति कई बार खुद को बेहद आत्मविश्वासी दिखाता है लेकिन अचेतन मन में खुद को लेकर गहरे संदेहों से घिरा होता है।

नकारे जाने के प्रति संवेदनशीलता व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और दूसरों के साथ उसके सामाजिक संबंधों को भी गहराई से प्रभावित करती है। एजेंसी

भाव पहचानने की क्षमता के आधार पर आंका

मुख्य शोधकर्ता डॉ. पैट्रीसिया कोर्जेनियोव्स्का और उनकी टीम ने प्रयोग के दौरान प्रतिभागियों को ऐसे छोटे वीडियो दिखाए गए जिनमें कंप्यूटर के जरिये किसी व्यक्ति का सपाट चेहरा धीरे-धीरे गुस्सा, घृणा, डर या खुशी जैसी भावनाओं में बदलता था।

■ चेहरों पर भावों की तीव्रता 2-2 प्रतिशत के बारीक अंतर से बढ़ रही थी। प्रतिभागियों को निर्देश दिया गया था कि चेहरे पर जैसे ही कोई भावना उभरती हुई दिखे, तुरंत बटन दबाएं।

■ नतीजों में देखा गया कि जिन लोगों का अचेतन आत्म-सम्मान कम था, उन्होंने गुस्से व घृणा के भावों को बेहद शुरुआती और हल्के स्तर पर ही पहचान लिया।

वर्क इंडिया रिपोर्ट में अहम खुलासा, मांग और अवसरों के बीच बड़ा अंतर कामकाजी दुनिया में महिलाओं की धमक फ्रंटलाइन नौकरियों में 43.5% हिस्सेदारी

मुंबई। देश की फ्रंटलाइन नौकरियों के लिए आवेदन करने वालों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर 43.5 फीसदी हो गई है, लेकिन सिर्फ 13 फीसदी नौकरी विज्ञापनों में महिलाओं को लक्षित किया गया। वर्क इंडिया रोजगार रिपोर्ट के मुताबिक, इससे महिलाओं की बढ़ती रोजगार रुचि और नियोक्ताओं की ओर से उन्हें अवसर देने के बीच अंतर सामने आता है।

रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल महिलाओं की हिस्सेदारी 40.4 फीसदी थी। अप्रैल से जून 2026 के बीच 772 शहरों में 6.5 लाख से



अधिक नौकरी विज्ञापनों और 98 लाख से ज्यादा आवेदनों के विश्लेषण के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें 50 से अधिक फ्रंटलाइन नौकरी श्रेणियां शामिल हैं। 65 फीसदी वृद्धि... जून और जुलाई 2026 में नौकरी के आवेदनों में सालाना आधार पर 65% वृद्धि हुई, जबकि नौकरी के विज्ञापनों की संख्या 40 से 48

ब्यूटीशियन और शिक्षण में सबसे ज्यादा आवेदन

महिलाओं की हिस्सेदारी ब्यूटीशियन की नौकरियों के लिए 86.6 फीसदी और शिक्षण पदों के लिए 80.7 फीसदी रही। वहीं बिक्री, कार्यालय, मार्केटिंग और ग्राहक सेवा जैसे क्षेत्रों में भी महिलाएं तेजी से आवेदन कर रही हैं। बिक्री क्षेत्र में सबसे ज्यादा 56 लाख से अधिक आवेदन मिले।

फीसदी बढ़ी। आईटी, एचआर, अकाउंट्स, बिक्री और कार्यालय संबंधी नौकरियों में प्रतिस्पर्धा अधिक रही। एजेंसी

आईआईटी, बॉम्बे में 22 वर्षीय बीटेक के छात्र की आत्महत्या क्षुब्ध करने वाली है। तीन दिनों तक चले छात्रों के भारी विरोध प्रदर्शन के बाद संस्थान ने अपने एंज प्रोफेसर को तत्काल प्रभाव से डीन पद से हटा दिया है। हालांकि, अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले जांच के नतीजों का इंतजार किया जाना चाहिए।

आत्महत्या और सवाल

दे

श के सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों में गिने जाने वाले आईआईटी, बॉम्बे में बीटेक द्वितीय वर्ष के छात्र साहिल वकोडे की आत्महत्या क्षुब्ध करने वाली तो है ही, उसके साथ जिस तरह तीन दिनों तक छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद अंततः संस्थान को एक प्रोफेसर को डीन पद से तत्काल प्रभाव से हटाने का फैसला लेना पड़ा, वह कई सवाल भी खड़े करता है। उल्लेखनीय है कि आत्महत्या के कुछ ही घंटे पहले मिड सेमेस्टर परीक्षा के दौरान छात्र को कथित तौर पर मोबाइल पर चैटजीपीटी का उपयोग करते हुए पकड़ा गया था। आत्महत्या के बाद परिजनों की शिकायत पर उक्त प्रोफेसर के खिलाफ एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। परिजनों का आरोप है कि उनके बेटे को पिछले काफी समय से जातिगत उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था। जबकि, संस्थान का कहना है कि उसके एससी/एसटी सेल को छात्र की ओर से कोई शिकायत नहीं

मिली। ऐसे में, जरूरी है कि इस पूरे मामले की गंभीर जांच हो और दोनों को कड़े से कड़ा दंड भी मिले। आजादी के बाद से देश ने शायद आईआईटी जैसे कुछ ही संस्थान बनाए हैं, जिनकी वैश्विक प्रतिष्ठा हो और जो सही मायनों में भरोसे के प्रतीक रहे हों। लेकिन, अगर एक ही कैपस में एक वर्ष के भीतर कई छात्रों ने आत्महत्या की हो, तो यह संस्थागत विफलता ही कही जाएगी। यही नहीं, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2018 से 2023 के बीच देश के विभिन्न आईआईटी संस्थानों में करीब 39 छात्रों ने आत्महत्या की। ये संस्थान आलोचनाओं से परे बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन ऐसे हादसों के कारणों को तोड़-मरोड़ कर भी पेश नहीं किया जाना चाहिए कि मूल समस्या ही उसमें तिरोहित हो जाए। इस तरह के संवेदनशील मामलों में राजनीति से बचना चाहिए और अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले जांच के नतीजों का इंतजार किया जाना चाहिए। कुछ भी हो, इस घटना ने आईआईटी परिसरों में छात्रों पर बढ़ते अकादमिक और सामाजिक दबाव की बहस

भारतीय तंत्रज्ञान संस्था मुंबई
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई



को फिर सामने ला दिया है। सर्वोच्च न्यायालय की राष्ट्रीय कार्यबल की अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार, आईआईटी के शिक्षकों में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है, जिन्हें मानसिक सेहत संबंधी समस्याओं से जूझ रहे विद्यार्थियों की पहचान और सहायता के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिला है। साहिल की आत्महत्या की निष्पक्ष जांच के साथ ही यह भी जरूरी है कि जिन संस्थानों को बनाने में दशकों लगे हैं, वे खुद आत्ममंथन करें और अपनी आंतरिक व्यवस्था को अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप बनाएं।

जीवन
अपनी
काम

मनुष्य
कितनी
खुबियों
व्यक्तित्व

**दूसरा
पहलू**



हाथ की नसों की सर्जरी शरीर में तो बदलाव लाती ही है, इसका असर दिमाग पर भी होता है। वहां उंगलियों का नक्शा नए सिरे से बन सकता है।

नसों की सर्जरी के बाद कैसे काम करता है दिमाग

■ केन वैलियर

AN

हमारे दिमाग में पूरे शरीर का एक व्यवस्थित 'नक्शा' मौजूद होता है। दरअसल, यह कोई असली तस्वीर नहीं होती, बल्कि दिमाग की गतिविधियों का एक खास पैटर्न होता है। इसमें शरीर के अलग-अलग हिस्सों को छूने पर दिमाग के अलग-अलग हिस्से सक्रिय होते हैं। इसे 'सोमैटोटोपिक मैप' कहा जाता है। मसलन, अंगूठे, तर्जनी और छोटी उंगली को छूने पर दिमाग में अलग-अलग जगहों पर गतिविधि होती है।



हाथ की नसें दिमाग व रीढ़ की हड्डी से हाथ तक संदेश पहुंचाती हैं। नस की सर्जरी के बाद दिमाग भी अपने काम करने के तरीके में बदलाव कर सकता है।



इन बदलावों के जरिये यह समझने में मदद मिल सकती है कि नस की चोट के बाद रिकवरी अलग-अलग लोगों में अलग क्यों होती है। इससे दिमाग की खुद को बदलने और नए संबंधों के अनुसार ढालने की क्षमता के बारे में भी जानकारी मिल सकती है।

अब एक नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया है कि हाथ की कटी नस की सर्जरी के बाद यह नक्शा बदल सकता है। यानी, नस के दोबारा जुड़ने के साथ दिमाग भी अपने काम करने के तरीके में बदलाव कर सकता है। हाथ की नसें दिमाग व रीढ़ की हड्डी से हाथ तक संदेश पहुंचाती हैं। अगर हाथ की कोई बड़ी नस कट जाए, तो सर्जरी के जरिये उसे जोड़ा जा सकता है। इसके बाद नस के नए रेशे (फाइबर) धीरे-धीरे बढ़ते हैं। इससे हाथ में महसूस करने की क्षमता कुछ हद तक वापस आ सकती है। हालांकि, नए रेशे हमेशा उसी रास्ते से नहीं जुड़ते, जिस रास्ते पर वे पहले थे। इसलिए, कभी-कभी दिमाग को मिलने वाला संदेश भी बदल सकता है। मसलन, तर्जनी को छूने पर किसी को ऐसा लग सकता है कि स्पर्श दूसरी उंगली पर हुआ है। इसी बदलाव को समझने के लिए शोधकर्ताओं ने हाथ की नस की सर्जरी करा चुके 21 लोगों के दिमाग के फंक्शनल एमआरआई की तुलना 30 सामान्य लोगों से की। नतीजे चौंकाने वाले थे। सर्जरी कराने वालों में उंगलियों से जुड़ा दिमाग का नक्शा बदल गया था, जो हर व्यक्ति में अलग-अलग था। हालांकि, बदलाव का मतलब यह नहीं कि हाथ कम काम करे। नस की चोट के बाद ठीक होने के लिए दिमाग का पुराने नक्शे पर वापस आना जरूरी नहीं है। दिमाग नए तरीके से काम करना सीख सकता है।

भविष्य में दिमाग के नक्शे में होने वाले बदलावों के जरिये यह समझने में मदद मिल सकती है कि नस की चोट के बाद रिकवरी अलग-अलग लोगों में अलग क्यों होती है। इससे दिमाग की खुद को बदलने और नए संबंधों के अनुसार ढालने की क्षमता के बारे में भी अहम जानकारी मिल सकती है।

-द कन्वर्सेशन

साक्षरता बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी



साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयास अपनी जगह हैं, लेकिन सिर्फ सरकार के भरोसे बैठना भी सही नहीं होगा।

अमित वैजनाथ गर्ग

मुद्रा

हा

ल ही में नीति आयोग की पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) की वार्षिक रिपोर्ट जारी हुई। इसके अनुसार, भारत में 14-18 साल की उम्र के लगभग दो करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। कक्षा 3-8 के करीब 11 फीसदी बच्चे स्कूल से बाहर हैं। इसके अलावा, हर साल 50 लाख से ज्यादा छात्र बोर्ड परीक्षा में फेल हो जाते हैं। रिपोर्ट कहती है कि बिहार, नगालैंड, मेघालय व असम जैसे राज्यों में स्कूल नहीं जाने वाले सबसे ज्यादा बच्चे हैं। देशभर में लगभग 7,993 स्कूल ऐसे हैं, जहां एक भी बच्चे का नया दाखिला नहीं हुआ है। रिपोर्ट बताती है कि स्कूल छोड़ने की सबसे ज्यादा दर 10वीं की पढ़ाई के बाद की है। देश में सरकारी स्कूलों के बंद होने की दर भी तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट में देश में शिक्षा, रोजगार और बेरोजगारी की असली स्थिति का लेखा-जोखा दिया गया है। यह रिपोर्ट 2021 में हुए नेशनल सैपल सर्वे के डाटा पर आधारित है। इसके अनुसार, देश में 29.1 करोड़ लोग



पढ़ाई कर रहे हैं। देश की अनुमानित साक्षरता दर 80.9 प्रतिशत तक पहुंच गई है। इसमें शहरी लोगों का प्रतिशत लगभग 90 फीसदी और गांवों का 77 फीसदी बताया गया है। देश में कुल 87.2 फीसदी पुरुष और 74.6 फीसदी महिलाएं पढ़ी-लिखी हैं। रिपोर्ट कुछ मामलों में देश में प्रगति की बात तो करती है, लेकिन अधिकतर मामलों में हालात अब भी चिंताजनक हैं। यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर स्टैटिस्टिक्स (यूआईएस) के आंकड़े बताते हैं कि दुनियाभर में वयस्कों की साक्षरता दर लगभग 88 प्रतिशत है, जबकि 15 से 24 साल के युवाओं में साक्षरता दर 93 प्रतिशत। इसमें

पिछले कुछ वर्षों में बढ़ोतरी हुई है। 1950 में दुनिया में लगभग 56 प्रतिशत शिक्षित युवा थे, जिनकी संख्या 1980 तक बढ़कर लगभग 70 फीसदी हो गई। इसके बावजूद, बिना पढ़े-लिखे युवाओं की अनुमानित संख्या 73.9 करोड़ बताई जाती है। इनमें दो-तिहाई महिलाएं भी शामिल हैं। यह आंकड़ा बताता है कि क्यों स्कूलिंग तक सबकी पहुंच बढ़ाने से साक्षरता में असमानता अपने-आप खत्म नहीं हो जाती। ये 73 करोड़ से ज्यादा युवा बुनियादी लिखना-पढ़ना भी नहीं जानते। इससे उनकी साक्षरता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

असल में साक्षरता में कमी का मुख्य कारण गरीबी, सामाजिक व आर्थिक असमानता तथा संसाधनों की कमी है। गरीब परिवारों के लिए दो वक्त की रोटी जुटाना प्राथमिकता होती है। ऐसे में, बच्चे पढ़ाई करने के बजाय कम उम्र में ही काम या मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वहीं ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में स्कूलों, योग्य शिक्षकों, किताबों और बुनियादी शैक्षणिक सुविधाओं का अभाव रहता है। कई समाजों में आज भी लड़कों की तुलना में लड़कियों की शिक्षा को कम महत्व दिया जाता है, जिससे महिलाओं में साक्षरता दर पिछड़ जाती है। तेज गति से बढ़ती जनसंख्या के कारण सरकार द्वारा दी जाने वाली शैक्षणिक सुविधाएं और योजनाएं हर व्यक्ति तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाती हैं। जागरूकता की कमी के कारण कई परिवारों में माता-पिता शिक्षा के महत्व को

नहीं समझ पाते और बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। असमानता के कारण कुछ वंचित समुदायों तक शिक्षा की पहुंच सुगम नहीं हो पाई है।

साक्षरता बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत, सामाजिक और सरकारी स्तर पर समन्वित प्रयास करने की जरूरत है। आधुनिक समय में डिजिटल और वित्तीय जागरूकता का प्रसार करना भी साक्षरता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बच्चों में शुरुआती स्तर पर सीखने की जिज्ञासा बढ़ानी होगी। गांवों और शहरों में मुफ्त पुस्तकालय स्थापित किए जाएं, ताकि हर व्यक्ति तक किताबों की पहुंच हो सके। साथ ही, विद्यालयों और घरों में बच्चों को पढ़ने के लिए सकारात्मक, प्रेरणादायक और संसाधन-युक्त वातावरण प्रदान किया जाए।

'विकसित भारत 2047' के विजन और आत्मनिर्भर भारत की नींव को मजबूत करने की दिशा में शिक्षा मंत्रालय का स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग स्कूल से बाहर और पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों की पहचान कर उन्हें दोबारा शिक्षा से जोड़ने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू करने जा रहा है। 2020 में जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2030 तक प्री-स्कूल से लेकर सेकेंडरी लेवल तक 100 प्रतिशत ग्रास एनरोलमेंट रेश्यो हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन, सवाल यह है कि क्या साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयास काफी हैं? आंकड़े बताते हैं कि केवल सरकार के भरोसे बैठना सही नहीं होगा। साक्षरता बढ़ाने के लिए सामाजिक संस्थाओं, शिक्षाविदों के साथ आम आदमी को भी आगे आना होगा, तभी शिक्षा को अलख जगाई जा सकती है।

edit@amarujala.com

कॉन्क्लेव में कैंसर के लिए विकसित की एआई तकनीक

अमर उजाला ब्यूरो

आईआईटी दिल्ली कॉन्क्लेव
में कई तकनीकें प्रदर्शित

नई दिल्ली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (आईआईटी दिल्ली) ने अपने सीएसआर कॉन्क्लेव में कैंसर की पहचान और चलने-फिरने की समस्याओं को दूर करने वाली कई तकनीकें प्रदर्शित कीं। इनमें एआई प्लेटफॉर्म और रोबोटिक एक्सोस्केलेटन प्रमुख थे। इस कार्यक्रम में उद्योग, सरकारी उपक्रमों, सीएसआर संस्थाओं, सरकार और शिक्षा क्षेत्र से 150 से अधिक विशेषज्ञ शामिल हुए।

कॉन्क्लेव में शोधकर्ताओं ने कैंसर की पहचान के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और सर्वाइकल कैंसर की शुरुआती जांच के लिए मिनी कोल्पोस्कोप पेश किया। बीमारी की पहचान में एआई आधारित प्लेटफॉर्म

भी दिखाए गए। रोबोटिक एक्सोस्केलेटन उन लोगों की गतिशीलता बढ़ा सकता है जिन्हें चलने में दिक्कत होती है। मेडिकल इमेजिंग, जीनोमिक्स और वैक्सीन जैसी अन्य तकनीकें भी प्रदर्शित की गईं। इनमें से कई तकनीकें अभी प्रोटोटाइप और परीक्षण के चरण में हैं।

कॉन्क्लेव में शोध को प्रयोगशाला से मरीजों तक पहुंचाने पर चर्चा हुई। एआई, डेटा उपयोग, मेडिकल तकनीकों के नियमन और शुरुआती शोध के लिए सीएसआर फंडिंग की भूमिका पर भी विचार-विमर्श किया गया। दूसरे हिस्से में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ शोध साझेदारी पर बात हुई।

यह रास्ता मुश्किल हो जाता है और कराने के निर्देश दिए थे।

कार्यकर्ता, सहायिका, लाभार्थी समुदाय की भागीदारी बढ़ाना है।

हर पांचवां नवजात कम वजन के साथ जन्मा

दिल्ली में वर्ष 2024-25 में 2.68 लाख नवजात जन्मे, इनमें 58,741 का वजन रहा कम

अमर उजाला ब्यूरो

20

ढाई से साढ़े तीन किलो तक सामान्य वजन

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, समय पर जन्म लेने वाले नवजात का वजन आमतौर पर ढाई से साढ़े तीन किलोग्राम के बीच रहता है। जन्म के समय ढाई किलोग्राम से कम वजन वाले बच्चे को कम जन्म वजन की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे नवजातों को सामान्य वजन वाले बच्चों की तुलना में अधिक निगरानी और देखभाल की जरूरत हो सकती है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जन्म के समय लड़कों का औसत वजन करीब 3.3 किलोग्राम और लड़कियों का करीब 3.2 किलोग्राम बताया गया है।

पांच साल में नवजात मृत्यु दर में बढ़ोतरी

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की अलग-अलग सालाना रिपोर्टों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में नवजात मृत्यु दर में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्ष 2019 में यह दर करीब 11 फीसदी थी, जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर करीब 12 फीसदी हो गई। वर्ष 2022-23 और 2023-24 में भी यह आंकड़ा करीब 12 फीसदी रहा। वर्ष 2024-25 की रिपोर्ट में वर्ष 2023 के आंकड़ों के आधार पर नवजात मृत्यु दर करीब 14 फीसदी दर्ज की गई। ऐसे में कम वजन वाले नवजातों की समय पर पहचान, उपचार और जन्म के बाद उचित देखभाल पर विशेष ध्यान देना जरूरी है।

पूर्वी दिल्ली। दिल्ली में हर साल लाखों बच्चों का जन्म होता है। इनमें बड़ी संख्या ऐसे नवजातों की भी है, जिनका जन्म के समय वजन सामान्य से कम रहता है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की वर्ष 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष के दौरान दिल्ली में करीब 2.68 लाख नवजातों का जन्म हुआ। इनमें 58,741 नवजातों का जन्म के समय वजन 2.5 किलोग्राम से कम था।

डॉक्टरों के अनुसार, कम वजन के साथ पैदा होने वाले हर बच्चे को कुपोषित मानना सही नहीं है। जन्म के समय कम वजन के कई कारण हो सकते हैं। इनमें गर्भावस्था के दौरान मां को पर्याप्त पोषण न मिलना, समय से पहले प्रसव, गर्भ में बच्चे की वृद्धि रुकना, मां में एनीमिया या हाई ब्लड प्रेशर जैसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं प्रमुख हैं। धूम्रपान और गर्भावस्था से जुड़ी अन्य जटिलताएं भी बच्चे के वजन को प्रभावित कर सकती हैं।

जीटीबी अस्पताल के एडिशनल मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. प्रवीण कुमार ने बताया कि ढाई

किलोग्राम या उससे अधिक वजन वाले नवजात को सामान्य वजन की श्रेणी में रखा जाता है; जबकि इससे कम वजन को कम जन्म वजन माना जाता है। ऐसे बच्चों को जन्म के बाद विशेष देखभाल, पर्याप्त पोषण और नियमित स्वास्थ्य जांच की जरूरत होती है। वह बताते हैं कि कि बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए गर्भावस्था के

दौरान मां का खानपान और स्वास्थ्य बेहद महत्वपूर्ण है। गर्भवती महिलाओं को संतुलित और पर्याप्त पोषण लेने के साथ नियमित स्वास्थ्य जांच करानी चाहिए। इससे गर्भ में बच्चे की वृद्धि पर नजर रखने और संभावित स्वास्थ्य समस्याओं की समय रहते पहचान करने में मदद मिल सकती है।

जल सुरक्षा मिशन के लिए विज्ञान, तकनीक और जनभागीदारी ज़रूरी

AI Image

जल हमें उन तरीकों से जोड़ता है, जिनमें बहुत कम दूसरे संसाधन जोड़ पाते हैं। नदियां प्रशासनिक सीमाओं को नहीं पहचानतीं। भूजल के स्रोत कई



सी. आर. पाटिल

समुदायों की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। आज होने वाली बारिश कल पीने के पानी, सिंचाई, भूजल या नदी के प्रवाह का आधार बनती है। इसलिए जल एक साझा

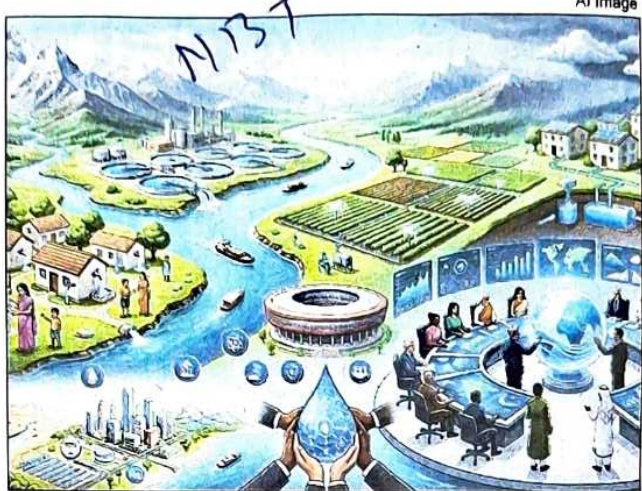
संसाधन है और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे सुरक्षित रखना हमारी साझा जिम्मेदारी है।

इसी भावना के साथ भारत 22 से 26 सितंबर 2026 तक नई दिल्ली में 9वें भारत अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह में वैश्विक जल समुदाय का स्वागत करेगा। इसका आयोजन जल शक्ति मंत्रालय कर रहा है। इस वर्ष की थीम

'जलवायु के प्रति लचीला जल प्रबंधन' है। जलवायु परिवर्तन के कारण जल चक्र लगातार अनिश्चित होता जा रहा है, ऐसे में यह विषय महत्वपूर्ण है।

भारत अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह ऐसा मंच है, जहां सरकारें, विशेषज्ञ, उद्योग जगत, समुदाय और अंतरराष्ट्रीय साझेदार अपने अनुभव, तकनीक और विचार साझा कर सकते हैं और भविष्य के लिए साझेदारियां बना सकते हैं। इसका उद्देश्य हालिया विभागीय जल शिखर सम्मेलन की भावना और उससे मिली सीख को आगे बढ़ाना भी है। इस सम्मेलन का विचार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रखा था। इसमें भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने जल क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा की और अपने अनुभव साझा किए।

भारत जल और स्वच्छता से जुड़ी योजनाओं को बड़े स्तर पर लागू करने का अनुभव लेकर इस संवाद में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण भारत में 15.9 करोड़ से अधिक घरों तक नल से पानी पहुंचाया गया है। वर्ष 2019 में ऐसे घरों की संख्या 3.23 करोड़ थी। जल जीवन मिशन 2.0 का मुख्य उद्देश्य जलापूर्ति के बुनियादी ढांचे को भरोसेमंद सार्वजनिक सेवा व्यवस्था में बदलना है। इसके तहत ग्राम पंचायतों और उनकी ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति सेवाओं के संचालन, रखरखाव और निगरानी के लिए सशक्त बनाया जा रहा है। इन्हें स्थानीय स्तर पर छोटी जल सेवा इकाइयों



के रूप में विकसित किया जा रहा है। 'जल सेवा आकलन' ग्राम पंचायत के नेतृत्व में की जाने वाली डिजिटल पहल है। इसके तहत हर घर जल वाले गांवों में पीने के पानी की नियमितता, पर्याप्तता, गुणवत्ता और स्थिरता का आकलन किया जाता है। इसमें ग्राम पंचायतों और गांव की संस्थाओं को आकलन की प्रक्रिया के केंद्र में रखा गया है।

नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा और उसकी सहायक नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसमें सीवेज से जुड़े बुनियादी ढांचे और प्रदूषण कम करने के साथ नदी के पर्यावरण को बहाल करने, जैव विविधता के संरक्षण और लोगों की भागीदारी पर ध्यान दिया गया है। इसके तहत 527 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें 367 पूरी हो चुकी हैं। इनके माध्यम से प्रतिदिन 4,263 मिलियन लीटर सीवेज के शोधन की क्षमता तैयार की गई है।

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए हैं। इसके दूसरे चरण में ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन पर ध्यान दिया गया है। घरों और सामुदायिक स्तर पर इस्तेमाल के बाद निकलने वाले पानी यानी ग्रे-वॉटर के प्रबंधन के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

इन सभी योजनाओं में 'जनभागीदारी' को महत्वपूर्ण माना गया है। 'जल संचय जनभागीदारी' और 'कैच द रेन' (वर्षा जल संचयन) जैसे अभियानों के माध्यम से जल संरक्षण को केवल सरकारी योजना तक सीमित न रखकर लोगों की आदत और जनआंदोलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जलवायु

के अनुकूल जल प्रबंधन तभी सफल हो सकता है, जब स्थानीय लोग इसे समझें, अपनी जिम्मेदारी मानें और इसे लंबे समय तक बनाए रखें।

भारत के अनुभव से यह भी सामने आता है कि जल संबंधी चुनौतियों का कोई एक समाधान नहीं हो सकता। हिमालयी राज्य की जरूरतें सूखे क्षेत्र से अलग होती हैं। इसी तरह तेजी से बढ़ते शहर की चुनौतियां ग्रामीण समुदाय से अलग होती हैं। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में भूजल स्तर बढ़ाने, सिंचाई में पानी का बेहतर इस्तेमाल, पेयजल व्यवस्था के सामुदायिक प्रबंधन और इस्तेमाल किए जा चुके पानी के दोबारा उपयोग जैसे क्षेत्रों में व्यापक अनुभव है।

तकनीक के साथ बेहतर आंकड़ों, वैज्ञानिक मॉडलों और डिजिटल प्रणालियों की मदद से पानी की उपलब्धता में बदलाव को समझने, संभावित खतरों का पहले से अनुमान लगाने और पानी का अधिक कुशलता से इस्तेमाल करने पर भी जोर होगा। 'सुजलम भारत' डिजिटल सार्वजनिक ढांचे का इस्तेमाल बेहतर योजना बनाने, जल स्रोतों को टिकाऊ बनाए रखने, कामकाज की निगरानी करने और नागरिकों की जरूरतों के अनुसार शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है।

22 से 26 सितंबर तक भारत मंडपम में होने वाला भारत अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह नेतृत्व, विज्ञान, योजनाओं का क्रियान्वयन, तकनीक, वित्त और जनभागीदारी को एक साझा मंच पर लाएगा। जलवायु परिवर्तन के कारण जल चक्र अधिक अनिश्चित हो सकता है, लेकिन हमारा जवाब सामूहिक, वैज्ञानिक, समावेशी और निरंतर होना चाहिए। जल हमारा साझा संसाधन है और जल सुरक्षा हमारी साझा जिम्मेदारी है।

(लेखक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं।)



डॉक्टर अब सर्जरी के दौरान ही देखेंगे इमेज

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

दरअसल, ब्रेनलैब और अमृता हॉस्पिटल ने सोमवार को एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। यह सेंटर ब्रेनलैब के Loop-X® मोबाइल इमेजिंग रोबॉट से लैस होगा। हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉ संजीव सिंह ने कहा कि ब्रेन और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी में बहुत ज्यादा सटीकता की जरूरत होती है। ऐसे मामलों में सर्जरी के

ऑपरेशन के वक्त शरीर की अंदरूनी बनावट देख सकेंगे

दौरान 2D और 3D इमेज मिलने से डॉक्टरों को एनाटमी देखने, इम्प्लांट की स्थिति जांचने और जरूरत पड़ने पर नई तस्वीर लेने में मदद मिलेगी। इसे सर्जिकल नेविगेशन सिस्टम के साथ भी जोड़ा जा सकता है। यह सेंटर केवल मरीजों के इलाज तक सीमित नहीं रहेगा।

ब्रेन और रीढ़ की हड्डी जैसी जटिल सर्जरी से गुजरने वाले मरीजों के लिए राहत की खबर है। फरीदाबाद के अमृता हॉस्पिटल में उत्तर भारत का पहला 'सेंटर ऑफ एक्सीलेस फॉर ब्रेन एंड स्पाइन' शुरू किया जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि सर्जरी के दौरान संबंधित हिस्से की नई इमेज ले सकेंगे। सर्जन ऑपरेशन के दौरान ही शरीर की अंदरूनी बनावट और सर्जरी में लगाए गए इम्प्लांट सही जगह पर लगे हैं या नहीं, यह देख सकेंगे। आमतौर पर अभी तक सर्जरी के बाद इमेजिंग की जरूरत पड़ने पर मरीज को अलग प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।

देश में सालाना जन्म 1974 के स्तर पर, 22 साल में 20% घटे

नई दिल्ली, प्रेड: भारत की आबादी से जुड़ी तस्वीर तेजी से बदल रही है। देश में हर साल जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या अब करीब 50 साल पहले के स्तर पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के हालिया पेपर के मुताबिक 2001 में देश में करीब 2.93 करोड़ बच्चों का जन्म हुआ था। 2023 में यह संख्या घटकर 2.32 करोड़ रह गई, यानी 20 प्रतिशत तक कम हो गई। यह संख्या लगभग उतनी ही है, जितनी 1974 में थी। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि देश की कुल आबादी घटने लगी है। भारत की अपेक्षाकृत युवा आबादी के कारण जनसंख्या में अभी जनसंख्या जड़त्व बना हुआ है। पर कम प्रजनन दर का असर आने वाले वर्षों में कामकाजी आबादी, बुजुर्गों की संख्या व देखभाल की जरूरतों पर दिखाई देगा।

यूपी-बिहार को छोड़ तस्वीर काफी बदली : आर्थिक सलाहकार परिषद के पेपर के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) 1.9 है।

● यूपी-बिहार को छोड़कर कुल प्रजनन दर 1.6, अमेरिका-यूरोप की जन्मदर के करीब

● पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद के पेपर में उभरी तस्वीर, दिल्ली में कुल प्रजनन दर 1.2 प्रतिशत



बिहार और उत्तर प्रदेश को अलग कर दें तो यह 1.6 रह जाती है, जो उत्तरी यूरोप के 1.5 और अमेरिका के 1.6 के करीब है। दक्षिण के कई राज्यों में स्थिति और नीचे है। केरल और तमिलनाडु की टीएफआर 1.3, आंध्र प्रदेश की 1.4, तेलंगाना और कर्नाटक की 1.5 है। पश्चिम बंगाल में भी यह 1.3 है। दिल्ली में यह 1.2 है। इन राज्यों में प्रजनन दर दो दशक से अधिक समय से प्रतिस्थापन स्तर से नीचे बनी हुई

है। आर्थिक सलाहकार परिषद के मुताबिक ऐसे राज्यों में अब बढ़ती उम्र, घटती युवा आबादी, कामगारों की उपलब्धता, पलायन और बुजुर्गों की देखभाल जैसी चुनौतियां ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। हालांकि, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 में देश की टीएफआर 2.0 बताई गई है। यह भी 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है। पापुलेशन फाउंडेशन आफ इंडिया (पीएफआइ) ने बदलती स्थिति को देखते हुए

जनसंख्या नियंत्रण के पुराने सोच से आगे बढ़ने की सलाह दी है। संगठन का कहना है कि परिवार नियोजन को आबादी घटाने के उपाय के बजाय प्रजनन संबंधी आजादी, बच्चों के जन्म में अंतर, मातृ-शिशु स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं से जोड़ना चाहिए। पीएफआइ की कार्यकारी निदेशक पूनम मुतरेजा के अनुसार राष्ट्रीय औसत के पीछे राज्यों, जिलों, ग्रामीण-शहरी आबादी और आय व शिक्षा के स्तर में मौजूद बड़े अंतर छिप जाते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों की युवा आबादी की जरूरतें केरल, तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश से अलग हैं। आर्थिक सलाहकार परिषद ने कम प्रजनन दर वाले राज्यों में नसबंदी से जुड़े प्रोत्साहन भुगतान खत्म करने और 'दो-बच्चे के नियम' से जुड़े अयोग्यता प्रविधानों की समीक्षा की सिफारिश की है।

केंद्र सरकार के सहयोग से 50 बेड का आयुष अस्पताल बनाएगी एनडीएमसी

सीवर की सफाई के लिए मशीनें खरीदने समेत कई अहम प्रस्ताव बैठक में मंजूर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: सोमवार को हुई नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) की बैठक में कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। आयुष की बढ़ती मांग को देखते हुए एनडीएमसी ने अपना 50 बेड का आयुष अस्पताल खोलने का निर्णय लिया है। इस अस्पताल में आयुष से संबंधी शोध भी होंगे। इस मौके पर बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने नवनियुक्त चेयरमैन मनोज कुमार द्विवेदी को पद व सत्य निष्ठा की शपथ भी दिलाई।

● कनाट प्लेस सबवे के सात पुराने एस्केलेटर बदलने के लिए 6.09 करोड़ रुपये मंजूर

● सीवर सफाई के लिए एनडीएमसी ने दो जेटिंग-कम-सक्शन मशीनें खरीदने का भी लिया निर्णय



एनडीएमसी की बैठक में नवनियुक्त चेयरमैन मनोज कुमार द्विवेदी को पद व सत्य निष्ठा की शपथ दिलाते दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा। साथ में सांसद बांसुरी स्वराज व एनडीएमसी उपाध्यक्ष कुलजीत चहल ● सौजन्य: एनडीएमसी

अस्पताल बनाएगी एनडीएमसी के अनुसार कनाट प्लेस सबवे के सात पुराने एस्केलेटर बदलने के लिए 6.09 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। पुराने एस्केलेटर खराब होने से लोगों को आवाजाही में दिक्कत आती थी। इसी तरह पंडारा रोड में पुरानी लोहे की पानी पाइपलाइन को नई लचीली लोहे की पाइपलाइन से बदलने का

भी निर्णय लिया गया है। सीवर की सफाई करवाने में कई बार दिक्कत आती है।

इसको देखते हुए एनडीएमसी ने दो आधुनिक जेटिंग-कम-सक्शन मशीनें खरीदने का भी निर्णय लिया है। वहीं, दिल्ली विशेष प्रविधान कानून 2011 की अवधि बढ़ाने से जुड़े प्रस्ताव को मंजूर कर केंद्र को

कर्मचारियों की समस्याओं का समयबद्ध तरीके से होगा निदान: मनोज कुमार द्विवेदी
प्रेसवार्ता में एनडीएमसी के चेयरमैन मनोज कुमार द्विवेदी ने कहा कि एनडीएमसी लगातार कर्मचारी हितेषी निर्णय ले रही है। इसी के तहत कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए हमने नियुक्ति संबंधी नियमों को नए सिरे बनाने का निर्णय लिया है। क्योंकि कई केंद्र में यह नियम ही नहीं है। इसलिए 10 केंद्र के संशोधित नियमों को मंजूरी देकर केंद्र सरकार को अधिसूचना के लिए भेज दिया है।

भेजने का भी निर्णय लिया गया। वर्तमान पार्किंग व्यवस्था को तीन क्लस्टर में बांटने को भी बैठक में मंजूरी दी गई है। अब इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की संख्या भी काफी बढ़ गई है। एनडीएमसी ने ईवी के लिए अपनी सभी पार्किंग में शुल्क में 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है।

अगली महामारी के लिए दुनिया अब भी तैयार नहीं

Miner Team

नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और लैंसेट की रिपोर्ट में दावा

रिपोर्ट

सिंगापुर, एजेंसी। कोविड संकट झेलने के बावजूद भविष्य में आने वाली महामारी के लिए दुनिया तैयार नहीं है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और लैंसेट प्राइम कमीशन की रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार केवल लैब और आपातकालीन योजनाएं बना लेने भर से दुनिया सुरक्षित नहीं होगी। जब तक हर नागरिक और कमजोर वर्ग तक सुरक्षा और वैक्सीन की समान पहुंच नहीं होगी, तब तक लोगों की जानें नहीं बचाई जा सकेंगी। यह रिपोर्ट न्यूयॉर्क में महामारी की तैयारियों पर 22 सितंबर से शुरू होने वाली संयुक्त राष्ट्र की बैठक से पहले जारी की गई है।

टीकों का समान वितरण जरूरी: रिपोर्ट के अनुसार, महामारी के दौरान यदि टीकों को अमीर देशों द्वारा जमा करने के बजाय दुनियाभर में आबादी के हिसाब से निष्पक्ष रूप से बांटा जाए, तो 27 लाख अतिरिक्त लोगों की जान बचाई जा सकती है।

27 लाख से अधिक लोगों की जानें बचेंगी अगर टीकों का समान वितरण आबादी के आधार पर किया गया



लोगों की जान बचाने के लिए ये सुझाव दिए गए

- महामारी से बचाव के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी को अनिवार्य और आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए।
- इंसानों और पर्यावरण की सेहत की सुरक्षा के लिए साझा और एकीकृत निगरानी प्रणाली बनाई जाए।
- केवल बीमारी रोकने पर नहीं, बल्कि गरीबी, भीड़भाड़ वाली जगहों और आजीविका जैसी बुनियादी समस्याओं को सुधारने पर काम हो।
- भ्रामक जानकारी से निपटने के लिए संवाद का रास्ता अपनाया जाए।

डब्ल्यूएचओ के निदेशक ने भी चेतावनी दी

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के महानिदेशक टेड्रोस गेब्रेयेसस ने भी दुनिया को महामारी को लेकर चेताया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि दुनिया महामारी को रोकने, उसकी तैयारी करने और उससे निपटने के लिए अभी भी पर्याप्त रूप से तैयार नहीं है। गुतारेस ने अपने अंतिम यूएनजीए से पहले लोगों से बेहतर दुनिया के लिए प्रयास जारी रखने और उम्मीद बनाए रखने की अपील की।

शोधकर्ताओं ने फ्लू जैसी महामारी के संभावित प्रकोप का मॉडल तैयार करके अध्ययन किया। इसके अनुसार यदि नई

बीमारी का टीका जल्द बना लिया जाता है, तो कुल मौतों का आंकड़ा घटाकर 2.39 करोड़ पर लाया जा सकता है।

लक्ष्मी को हासिल नहीं कर सके उसके सहयोगियों के साथ युद्ध को दोबारा खोलने में उसकी नाकामी है। राष्ट्रपति के कार्यक्रमों का साझा वीडियो हाउस टेलीविजन पूल के अध्यक्ष और वीडियो

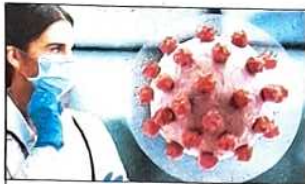
झारखंड में मिला रूबेला का पहला मरीज, सरकार सतर्क

संक्रमण

रंजन

रांची। झारखंड में रूबेला वायरस (जर्मन खसरा) ने दस्तक दी है। राज्य में रूबेला का पहला मरीज मिला है। सिमडेगा की 10 वर्षीय बच्ची में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके बाद राज्य में स्वास्थ्य महकमा सक्रिय हो गया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड में राज्यस्तरीय वॉर रूम बनाया गया है। साथ ही राज्यभर में टीकाकरण अभियान का भी संचालन शुरू कर दिया गया है। राज्य में खसरा से पीड़ित 15 मरीज भी मिले हैं। ये मरीज पश्चिम बंगाल से सटे पूर्वी सिंहभूम, पाकुड़ समेत राज्य के तीन-चार जिलों के हैं।



हवा से फैलता है

रूबेला हवा से फैलने वाला संक्रमण है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है, तो हवा में फैली ड्रॉपलेट्स (बूंदों) के माध्यम से यह वायरस सांस के जरिए दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है।

राज्य टीकाकरण पदाधिकारी विजय किशोर रजक ने बताया कि कुछ जिलों में खसरा का आउटब्रेक हुआ है। स्थिति नियंत्रित कर ली गई है। वहीं मिजल्स-

10 वर्षीय बच्ची में संक्रमण की पुष्टि हुई सिमडेगा में

कुपोषण, अन्य बीमारियां बनाती हैं इसे जानलेवा

रूबेला एक संक्रामक बीमारी है, जिसे आम भाषा में 'जर्मन खसरा' कहा जाता है। इस संक्रमण के लक्षण सामान्य खसरे से मिलते-जुलते होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, यह सामान्य खसरे से कम गंभीर होता है लेकिन यह तब जानलेवा बन जाता है, जब प्रभावित बच्चों को देखभाल नहीं मिल पाती।

रूबेला (एमआर) टीकाकरण की सूक्ष्म स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। ठेठईटांगर प्रखंड के मुंडाटोली में एक बच्चों में संक्रमण की पुष्टि के बाद और

15 मरीज खसरा के भी मिले हैं तीन से चार जिलों में

मध्य प्रदेश के बेलाघाट में 31 से अधिक मौतें

मध्य प्रदेश के बेलाघाट में बैगा जनजाति बहुल बिरसा और बैहर ब्लॉकों में इसी साल जून से अगस्त के बीच रूबेला संक्रमण के साथ निमोनिया, मलेरिया और दिमागी बुखार ने कई बच्चों को चपेट में ले लिया था। 431 बच्चों को भर्ती किया था। जून से अगस्त तक 31 बच्चों की जान गई।

एक्टिव केस की खोज जारी है। स्थानीय स्वास्थ्य संस्थानों को प्रभावित इलाके में मामलों की लाइन लिस्ट अपडेट करने का निर्देश दिया गया है। वहीं बच्ची

ऐसे कर सकते हैं बचाव

- बच्चों को खसरा-रूबेला (एमआर) के निःशुल्क टीके की दोनों खुराक अनिवार्य रूप से लगवाएं
- किसी कारणवश बचपन में टीका छूट गया हो तो डॉक्टर की सलाह लेकर 15 वर्ष की आयु तक लगवा सकते हैं
- महिलाओं और गर्भावस्था के दौरान रूबेला की जांच अनिवार्य रूप से करवाएं
- संक्रमित या संदिग्ध व्यक्ति आइसोलेशन का पालन करें, शरीर पर चकते निकलें तो पांच दिन तक बिल्कुल अलग रहें
- संक्रमित मरीज और उनकी देखभाल करने वाले लोग मास्क का हर समय उपयोग करें

में रूबेला की पुष्टि होने के बाद सिमडेगा के सिविल सर्जन ने ठेठईटांगर रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को दिशा-निर्देश दिए।

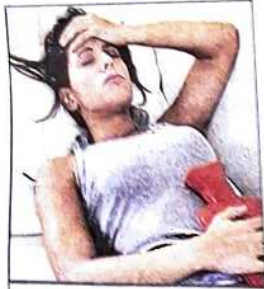
शोध | गोरखपुर एम्स के कई विभागों द्वारा 18 से 30 साल की महिलाओं पर किए गए अध्ययन में सामने आई जानकारी

पीरियड के बाद तनाव से बढ़ रहा है उच्च रक्तचाप

■ नीरज मिश्र

गोरखपुर। पीरियड (मासिक चक्र) के अलग-अलग चरणों में महिलाओं में तनाव का असर अलग-अलग हो रहा है। पीरियड के बाद तनाव से बीपी बढ़ रहा है और महिलाएं चिंता भी ज्यादा कर रही हैं।

एम्स के शोध में मासिक चक्र के ल्यूटियल फेज यानी ओव्यूलेशन के बाद वाले चरण में तनाव के प्रति शरीर और मानसिक प्रतिक्रिया अधिक देखी गई। तनाव देने के बाद डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर (नीचे वाला बीपी) बढ़ा मिला, जबकि चिंता का स्तर भी अधिक पाया गया। शोध इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी,



पैथॉफिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी में प्रकाशित हुआ है। यह अध्ययन एम्स के फिजियोलॉजी, मनोचिकित्सा, नर्सिंग और माइक्रोबायोलॉजी विभागों के शोधकर्ताओं ने संयुक्त रूप से किया है। शोधकर्ताओं ने बताया कि शोध में

इलाज में मददगार हो सकता है अध्ययन

शोधकर्ताओं का मानना है कि महिलाओं में तनाव, चिंता से जुड़ी दूसरी समस्याओं का आकलन करते समय मासिक चक्र के चरण को भी ध्यान में रखना सबसे अहम है। इससे भविष्य में महिलाओं को उसी अनुसार स्ट्रेस मैनेजमेंट और इलाज को जरूरत हो सकती है। इस दौरान अगर उन्हें कोई और दिक्कत आती है तो इन्हें भी ख्याल रखना होगा। अध्ययन आईसीएमएच के शॉर्ट टर्म स्ट्रुक्चरल प्रोग्राम के तहत किया गया था। शोध में डॉ. प्रशांत मिश्रा, डॉ. चारुसिला रुक्मादेव, डॉ. मनोज पुष्पीराज, डॉ. गीता मोहन, डॉ. अतुल रुक्मादेव, डॉ. सुंदर मोहनराव और डॉ. सामीक्षा निषाद शामिल रही।

18 से 30 वर्ष की 104 ऐसी महिलाओं को शामिल किया गया, जिनका मासिक चक्र सामान्य था।

अध्ययन में गर्भवती, स्तनपान कराने वाली, मासिक चक्र में गड़बड़ वाली और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं

वाली महिलाओं को शामिल नहीं किया गया। शोधकर्ताओं ने इसके बाद मासिक चक्र के अलग-अलग चरणों में महिलाओं को जांच की। इसमें आराम की स्थिति में शराब प्रेशर और हार्टरेट जांच की गई। चिंता और

एम्स की टीम सामाजिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अहम शोध कर रही है। इसमें नई जानकारियां हासिल हुई हैं। इससे महिलाओं के इलाज में काफी मदद मिलेगी।

- डॉ. दिनेश दास, कार्यकारी निदेशक
स्वयंसेवा केंद्र

मानसिक तनाव का आकलन करने के लिए मानक प्रश्नों का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद कोलॉइडल रेशर करवाया गया, जिससे उन्हें मनो के संकेतों के संकेत करने के लिए निर्देशन को देखा गया।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने पर विचार

नई दिल्ली, प्र.सं। 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत दिल्ली सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के योगदान को सम्मान देने के लिए 'आंगन का मिलन' कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। साथ ही, मानदेय को बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर बच्चों, महिलाओं और परिवारों तक सरकार की सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनके समर्पण और योगदान को सम्मान देना सरकार की जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए दिल्ली की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम 23 सितंबर से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विशेष सम्मान किट भी तैयार की गई है। इसमें बैग,

10

हजार से
ज्यादा केंद्र हैं
दिल्ली में

22

हजार
कार्यकर्ता
और सहायक

यूनिफॉर्म, इंसुलेटेड पानी की बोतल, कैप, प्राथमिक उपचार पाउच और छाता होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि करीब 25 हजार निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस पहल से जोड़ा जा सके। इनमें विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि, लाभार्थी, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, माता-पिता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायक आदि शामिल होंगे। इन कार्यक्रमों को 9वें राष्ट्रीय पोषण माह 2026 से भी जोड़ा गया है।

कुछ अलग | उपग्रह से पता चला कि 15 से 20 सितंबर के बीच छह राज्यों में पराली जलाने की 19 घटनाएं हुईं

सांसें का सुकून खत्म, धधकने लगी पराली

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। मौसम में बदलाव और मानसून के कमजोर पड़ने के साथ ही पंजाब, यूपी, हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं शुरू हो गई हैं। इसका असर वायु गुणवत्ता पर भी दिखने लगा है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के क्रीम्स (कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन एग्रोइकोसिस्टम मॉनिटरिंग एंड मॉडलिंग फ्रॉम स्पेस) उपग्रह निगरानी के अनुसार 15 से 20 सितंबर के बीच छह राज्यों में पराली जलाने की 19 घटनाएं दर्ज की गईं। इनमें 14 घटनाएं पंजाब, चार उत्तर प्रदेश और एक दिल्ली में हुईं। पराली जलाने से निकलने वाला धुआं हवा की दिशा

वायु गुणवत्ता सूचकांक बढ़ने लगा



और मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण दिल्ली-एनसीआर तक पहुंच सकता है। इस समय दिल्ली की ओर आने वाली हवाएं मुख्य रूप से उत्तर-पश्चिमी हैं, इसलिए पंजाब में जलने वाली पराली का असर राजधानी की

पिछले साल पराली जलाने के मामले

पंजाब	5114
हरियाणा	662
उत्तर प्रदेश	7290
दिल्ली	05
राजस्थान	2890
मध्य प्रदेश	17067
कुल	33028

हवा पर एक सप्ताह में दिखाई देने की आशंका है। 15 अक्टूबर से 25 नवंबर के बीच दिल्ली के प्रदूषण में पराली के धुएं की हिस्सेदारी मौसम की अनुकूल परिस्थितियों में 40 फीसदी से अधिक तक पहुंचती रही है।

पंजाब और हरियाणा में घटे, यूपी में बढ़े मामले



पिछले कुछ वर्षों में पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं

में कमी आई है, लेकिन समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। वहीं, उत्तर प्रदेश में पिछले दो-तीन वर्षों में ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में धान की कटाई के बाद खेतों में बचे अवशेष जलाने की घटनाएं सामने आती रही हैं।

Joining hands for water security as warming rises

Water connects us in ways few other resources do. Rivers do not recognise administrative boundaries, aquifers may sustain several communities, and rain that falls today becomes tomorrow's drinking water, irrigation source, groundwater or river flow. Thus, securing water for our future generations is a shared responsibility.

It is in this spirit that India will welcome the global water community to the 9th India International Water Week, organised by the ministry of Jal Shakti on September 22-26, 2026 in New Delhi. The theme, Climate Resilient Water Management, is particularly relevant at a time when the climate crisis is making the water cycle increasingly unpredictable. India International Water Week is a platform where governments, experts, industry, communities, and international partners build partnerships for the future. It also seeks to further the spirit and lessons from the recent Departmental Summit on Water, an idea mooted by Prime Minister Narendra Modi, where India's states and UTs came together to deliberate on the sector's challenges, share experiences, and identify the way forward.

India brings to this dialogue extensive experience of implementing water and sanitation programmes at scale. The Jal Jeevan Mission has brought tap water to more than 15.9 crore rural households, from 3.23 crore households in 2019. Jal Jeevan Mission 2.0 is centered on transforming water-supply infrastructure into dependable public service delivery systems. Gram Panchayats and its Village Water & Sanitation Committees (VWSCs) are being empowered as local micro utilities for operating, maintaining and monitoring rural water services. Jal Seva Aankalan, a Gram Panchayat-led digital drinking water service functionality assessment, marks a decisive shift from infrastructure creation to sustained service delivery, placing Gram Panchayats and village institutions through Jan Bhagidari at the centre of assessing the regularity, adequacy, quality and sustainability of drinking water supply in Har Ghar Jal villages. Through the Namami Gange Programme, India seeks to rejuvenate the river Ganga and its tributaries by combining sewage infrastructure and pollution abatement with ecological restoration, biodiversity conservation and people's participation.

Under Swachh Bharat Mission-Grameen, more than 12 crore toilets have been constructed in rural areas. The second phase of this mission has also focused upon solid and liquid waste management. Across these programmes runs a common thread — Jan

Bhagidari, with the conviction that public policy is strongest when people move from being beneficiaries to becoming partners.

The same approach guides our water-conservation efforts. Through initiatives such as Jal Sanchay Jan Bhagidari and the Catch the Rain campaign, our objective is to make water conservation a people's movement.

India's experience also teaches us that there is no single solution to water challenges. Needs vary depending on geography, urbanisation, and community needs, among other factors. This diversity makes our states and UTs a rich reservoir of experience in groundwater recharge, irrigation efficiency, community management of drinking-water systems and wastewater reuse. When such experiences are shared, successful local solutions can travel far beyond the places where they began.



CR
Patil

Discussions at India International Water Week will span river-basin and aquifer management, wastewater reuse, water-use efficiency, forecasting, early-warning systems and environmental flows.

Better data, modelling and digital systems can help us understand how water availability is changing, anticipate risks and improve efficiency. But technology delivers its greatest value when it enables better

decisions by governments, local institutions and communities. This is why the participation of practitioners, start-ups and young people is especially important. Under JJM's institutional reform, the Sujalam Bharat digital public infrastructure ecosystem is leveraging data and technology to improve planning, source sustainability, performance monitoring and citizen-centric governance.

Public investment will remain fundamental, but climate-resilient water infrastructure will increasingly require innovative financing, responsible private participation and partnerships that mobilise resources while keeping public purpose at its core.

As the climate crisis brings more uncertain rainfall, intense precipitation, prolonged dry periods, floods and groundwater stress, resilience will require source sustainability, better science and forecasting, adaptive infrastructure, sound institutions and informed communities. This is the larger purpose of India International Water Week: to bring leadership, science, implementation, technology, finance, and public participation to a common table. The climate crisis may make the water cycle more uncertain. Our response cannot be uncertain. It must be collective, scientific, inclusive and sustained.

CR Patil is Union minister of Jal Shakti.
The views expressed are personal

Parental demand, education markets and the spread of ideologies

Hindutva is spreading through everyday interactions in the education market, with parents playing a role in shaping school decisions; marketisation allows majoritarian preferences to be expressed as consumer demands, with schools accommodating them while sidelining minority concerns

Rebecca Rose Varghese

Arora-Kukreja Ritika, 'Hindutva by Other Means: The Educational Market and the Politics of Demand', *Economic and Political Weekly*, Vol 61 Issue No. 34, August 22, 2026

Recently, an advertisement for a jewellery brand featuring a Bollywood actress during Raksha Bandhan was taken down by the brand following public outrage over her attire, which some considered insufficiently modest for a traditional festival. While there were debates over whether her dressing should be judged in such a manner, the brand eventually took down the advertisement and apologised to a section of the public, responding to pressure from a majoritarian opinion.

In another incident, a Muslim IPS officer in Bengal was transferred after Hindutva groups criticised her for using an Islamic greeting on social media. While the government and its nationalist ideologies may have their own role in such incidents, public pressure in this case was an important factor that resulted in her immediate transfer.

In both these cases, the institution or management responded to the majoritarian or dominant public view.

When we think about how ideologies spread and become embedded in everyday life, we often assume that the state apparatus plays the primary role, using its institutions and various forms of authority to promote particular ideas. What we often overlook, however, is the influence of the majoritarian public itself.

Public pressure, consumer choices, social expectations and everyday interactions can also become important channels through which an ideology is reproduced and normalised.

One of the best locations to examine the spread of political and religious ideologies is schools, because history shows how the moulding of young minds can become a central aspect of ideological reproduction.

Studies have shown how state apparatuses have often been used to promote particular political and social ideologies through education. Hindutva is one such right-wing political ideology of Hindu nationalism that seeks to define India's cultural and national identity through Hindu values and heritage and influence public policy, which the state has promoted through schools in India.

The Bharatiya Janata Party (BJP)-led governments, both during the 1998-2004 period and from 2014 to date, have used the state's power over curriculum and regulation to advance a particular vision of Indian nationhood. This literature has produced a robust analytical vocabulary to think of saffronisation as a product of a state-led project: the deliberate use of state institutional capacity to reshape the content and culture around education in a way that resonates with the Hindu majoritarian conception of the nation.

But is this the only way Hindutva enters schools? Are there no other players?

While the state may have a direct role in shaping government schools, what about spaces where its hold is less direct, particularly private urban schools that often present themselves as modern, cosmopolitan and removed from such



Growing influence: In the education market, parents express their preferences, which school management responds to and incorporates into its decisions. THILAK KAMAT

ideological concerns?

Think of the first two examples in the context of such schools. This is what author Ritika Arora-Kukreja does in her article.

The article is particularly relevant as it examines other factors that have helped push Hindutva ideology into schools. The paper argues that Hindutva is increasingly spreading through everyday interactions in the education market, not just through government policies or Hindutva organisations. This side of education has largely been overlooked by both the literature on marketisation and the literature on saffronisation.

Through in-depth interviews and focus group methods with households with children, and interviews with school leaders across private schools in Delhi-NCR between April and September 2022, the author analyses the increasing role of parents as actors pushing for Hindutva ideologies to spread in Indian schools.

From regulation to market demand

The Nehruvian model of education after independence was such that the state provided, regulated and directly controlled institutions. But after the 1991 liberalisation reforms, the relationship between the state and institutions, especially schools, changed drastically. With privatisation, the middle and upper-middle classes, especially in urban India, started attending private schools, where state control was extremely limited. The author explains that in Delhi, where she did her study, private-school enrollment at the primary and middle levels increased from around 30% in 2014-15 to over 46% in 2019-20. So while the state did not disappear and still continued to spread ideologies through

the curriculum and syllabus, its role in directly influencing and promoting ideologies had its limits.

The state was then replaced by market demands, especially those of the dominant middle and upper-middle classes. Parental preferences started taking precedence over the state apparatus and shaped decisions made by school management.

For instance, if parents do not approve of the appointment of a Muslim teacher due to the fear that they may promote Islam, they are not admitted. Or if the majority of parents are vegetarian, the school may make a rule that non-vegetarian food should not be brought for lunch, which inevitably affects children from other religions and cultures. Schools succumb to the demands of the dominant group while sidelining minorities, fearing the repercussions of not doing so.

The Hindu customer

Strong competition between schools, combined with the majoritarian population in a region, creates what the author calls the "Hindu customer", whose demands have to be met by school management. Highlighting Hindu festivals in schools, giving holidays for them, deliberately not admitting students from certain religious groups, and attempting to ban the hijab from schools are some examples. The author calls this "hyper-accountability".

While marketisation is supposed to make schools more accountable by giving parents more power and making schools depend on parent satisfaction, in this context, schools are focused on satisfying the majority. The concerns of minority families are ignored, as their dissatisfaction will have a smaller

economic impact on schools.

Here, it is the Hindu customer who is being satisfied. Instead of being seen just as a religious identity, they attain the identity of a powerful customer in the education market, whose demands cannot be ignored.

Their economic power, combined with the growing political legitimacy of Hindu nationalism, ensures that schools meet their demands while trying to present them as reasonable. For instance, instead of citing religious reasons, schools use hygiene to justify banning non-vegetarian food and security to justify banning the hijab, while the same concerns are not applied to visual symbols of other religious groups.

Political demands as choices

One of the ways in which such demands are justified and seen as rational or reasonable is through what the author calls the "depoliticisation of choices". The demands or preferences of parents are seen as individual, private consumer choices rather than politically coloured ones. Marketisation literature often presents this in simple terms: the parent has a demand, and the market responds to it.

It therefore becomes important to understand how these preferences are formed. The author explains how citizens are influenced on a daily basis by ideas of Hindu nationalism through news media, social media, neighbourhoods and other forms of political socialisation. Their choices about education therefore also reflect these political and cultural ideas.

The market does not necessarily create these preferences. Instead, it provides a system where such preferences can be expressed as legitimate consumer demands and accommodated by schools that depend on satisfying their consumers. The author explains that the education market does not only reproduce class inequalities. In contemporary India, it can also provide an institutional space for religious-nationalist preferences to enter and shape education.

Challenging the ideology spread

Challenging the spread of Hindutva or other religious ideologies in schools is important because education shapes young and impressionable minds and can influence how they understand religion and society. To do so, it is necessary to understand how such ideologies enter educational spaces.

Existing saffronisation literature has mainly focused on the role of the state and political organisations. The author draws attention to another channel, which she calls "bottom-up Hindutva". Unlike state-led Hindutva, which spreads from state institutions and political organisations into society, "bottom-up Hindutva" describes a process in which preferences and demands from society shape institutions. In the education market, parents express their preferences, which school management responds to and incorporates into their decisions. The paper is therefore important because it highlights other ways in which religious ideologies can spread, which need to be closely examined to understand and challenge their influence in education.

(Rebecca Rose Varghese is a freelance journalist)



AJAY MATHUR

Nepal's climate call is a test for India

FOR DECADES, India's diplomatic ties with Nepal during natural calamities followed a well-known script. When cloudbursts, landslides, or flash floods devastated the Himalayan nation, New Delhi acted as a friendly "first responder". However, after the recent catastrophic flash floods, Nepal's leadership has moved away from a paradigm of ad-hoc relief to a framework of climate justice and financial liability. Kathmandu has appealed to the UN-backed Fund for Responding to Loss and Damage while calling on developed countries to deliver compensation and concessional climate finance, and pressing regional neighbours, including China and India, for cooperation on preparedness, data sharing and resilience. It has clarified that it is not seeking damages from any single country, but the expectation placed on its neighbours is unmistakable. Prime Minister Balendra Shah will take this case to the UN General Assembly on September 24.

This shift presents India with a dilemma. As a leading voice of the Global South, India has historically argued that the Global North bears sole responsibility for funding climate loss and damage. Yet, as a rising regional power whose emissions footprint and infrastructure investments are tied to the Third Pole's fragile ecology, India can no longer rely on global support alone. New Delhi must evolve from a donor during crises into a co-underwriter of regional climate justice.

Global climate finance mechanisms are unsuited for fast-moving, compounding ecological dis-

23

India can construct regional institutions that deliver the substance of loss and damage funding without getting bogged down in fault-based compensation terminology

asters. Consider the UN Green Climate Fund's (GCF) track record. A \$49.9 million project designed to protect vulnerable Nepalese communities from glacial lake outburst floods sat in the GCF pipeline for over seven years. By the time bureaucratic approvals cleared, the waters had already broken. Similarly, while the UN Loss and Damage Fund was created to address irreparable climate impacts, its capital reserves remain a drop in the ocean compared to actual costs. Nepal faces a reconstruction bill of nearly 10 per cent of its GDP. Downstream and mountain nations are applying the Common But Differentiated Responsibilities principle locally, pointing out that adjacent, high-emitting economic engines share an immediate physical footprint in their backyard.

For New Delhi, this is an uncomfortable precedent. India's per capita emissions remain low, its historical contributions to global warming are minimal compared to the West, and it is itself a climate change victim. Accepting direct "liability" or paying explicit "climate damages" could expose India to similar claims from other countries, while weakening its leverage against the Global North. Rejecting Kathmandu's appeals, however, carries a geopolitical cost. China is stepping up its climate and green outreach across the Himalayas. An evasive response could turn Nepal's people away from India and give Beijing more room.

India must transcend the false choice between total legal liability and passive humanitarian aid. As a

dominant middle power, India can construct regional institutions that deliver the substance of loss and damage funding without getting bogged down in fault-based compensation terminology. Working through frameworks like the New Development Bank, the Asian Infrastructure Investment Bank, BIM-STEAC, or a Third Pole Compact, India should champion a South Asian Resilience and Insurance Facility. Operating as a rapid-payout insurance pool, it would release funds upon satellite detection of threshold climate triggers, bypassing diplomatic wrangling. This ensures predictable finances for both Nepalese reconstruction and annual Indian disaster allocations.

India must make joint projects resilience-first, directing part of infrastructure funds to an adaptation fund for climate-proof local works, safer slopes and mountain livelihoods. India's space capabilities should be leveraged to create a real-time, open-access early warning system for the Himalayan belt. Co-owning GLOF monitoring data and lake volume tracking with Nepalese agencies transforms tactical intelligence into a shared regional security asset.

In this new phase of climate geopolitics, countries like India and China stand at a pivotal crossroads. By pioneering localised loss and damage mechanisms, co-underwriting regional resilience, and institutionalising transboundary safety, New Delhi can demonstrate a new paradigm of middle-power leadership.

The writer is professor, School of Public Policy, IIT Delhi